

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास - श्री दिनेश कुमार मीना ( आर.ए.एस. )

प्रकरण सं. 117/2023/राजस्व वाद

दायरा दिनांक 04.10.2023

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

- वादी

बनाम

1. गुलाबचन्द पि. पुरुषोत्तम जाति ब्राहमण नि. उन्हेल तहसील सुनेल
2. रीना श्रुंगी पत्नि अजय श्रुंगी जाति ब्राहमण नि. उन्हेल तहसील सुनेल
3. हर्षवर्धन श्रुंगी पि. ओमप्रकाश जाति ब्राहमण नि. उन्हेल तहसील सुनेल

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 177-178 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति -

पेरोकार सरकार - तहसीलदार सुनेल

प्रतिवादीगण/खातेदारान - श्री हुकुमचन्द कुमावत

निर्णय

दिनांक : 10.01.2025

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उन्हेल तहसील उन्हेल में ख.नं 1256 रकबा 1316 हैक्टर खातेदार उपरोक्त जाति ब्राहमण नि. उन्हेल के खाते दर्ज है। सुविधा की दृष्टि से वाद में इस आराजी को वादग्रस्त आराजी कहा गया है। यह है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी को कृषि कार्य करने हेतु दी गई थी। यह है कि प्रतिवादी ने उक्त आराजी पर खनन कार्य प्रारंभ कर दिया जिससे यह भूमि खेती करने योग्य नहीं रही है। यह है कि यह आराजी खातेदारों द्वारा कृषि भूमि को अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में लेकर कृषि शर्तों का उल्लंघन किया है, इससे यह भूमि कृषि उपयोगार्थ नहीं रही। यह है कि दिनांक 09.05.2023 को भूअभि.निरी. ढाबलाखीची व पटवारी हल्का उन्हेल द्वारा मौका देखे जाने पर जानकारी में आया है। यह है कि श्रीमान को वाद श्रवण अधिकार है। यह है कि राजस्थान सरकार का लैण्ड होल्डर होने के कारण वाद प्रस्तुत किया गया है। यह है कि इस वाद में किसी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं है। अतः वादग्रस्त आराजी को कृषि

4  
उपखण्ड अधिकारी  
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)





का कथन गलत अंकित किया है। भूमि सुधार का कार्य खातेदारों ने किया है। यह भी इन्कार है कि खातेदार प्रतिवादीगण ने कृषि भूमि को अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में लेकर कृषि शर्तों का उल्लंघन किया हो। उक्त रकबा भूमि प्रारम्भ से आज तक कृषि के उपयोग में ही काम आ रही है। इस कारण यह कथन बाद में गलत अंकित किया है। यह कि प्रतिवादीगण के खसरा संख्या 883 क्षेत्रफल 2.0108 हैक्टेयर बगैर बरानी स्वयं भूमि में प्रतिवादीगण का कुआं लगा हुआ है। जिससे कृषि में सिंचाई करने के लिए पानी पहुँचाने में खसरा संख्या 1256 का कुछ भाग जो ढलान के रूप में है। वहाँ पानी नहीं पहुँचने के कारण इस ढलान वाले भाग की मिट्टी को निकालकर खेत को समतल किये जाने के लिए खुदाई की गई थी जो कृषि सुधार कार्यों के अन्तर्गत आती है। यही कार्य प्रतिवादीगण द्वारा किया गया ताकि खसरा संख्या 1256 पर आसानी से बिना अवरोध के सिंचाई का पानी कुएँ से सम्पूर्ण क्षेत्रफल भूमि पर पहुँच सके। यही प्रयत्न प्रतिवादीगण द्वारा किये गये हैं। इस कारण वादी का कथन असत्य है। यह कि खसरा संख्या 1256 रकबा 1363 हैक्टेयर भूमि में कृषि, कृषि घास, फसल का उत्पादन किया जाता रहा है। इस भूमि पर किसी भी क्षण खनन कार्य नहीं किया है। इस कारण वादी का वाद भी निरस्त होने योग्य है। अतः जवाब दावा पेश कर माननीय न्यायालय से प्रतिवादीगण प्रार्थना करते हैं कि वादी द्वारा पेश वाद को बाद सुनवाई साक्ष्य की रोशनी में खारिज किये जाने की कृपा करें।

3. वाद पत्र के समर्थन में परोकार सरकार/वादी द्वारा पटवारी हल्का उन्हेल की मौका रिपोर्ट, ग्राम उन्हेल की जमाबंदी सं. 2074-77 के खाता सं. 534, की प्रमाणित नकल एवं खसरा गिरदावरी की नकल, नक्शा ट्रेस नकल संलग्न की।

4. प्रतिवादीगण/खातेदारान अपने जवाब के समर्थन में वादग्रस्त भूमि के मौके के फोटोग्राफस दिनांक 18.12.2024 पेश किये।

5. वादी/तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्रांक 1045 दिनांक 15.10.2024 से पुनः जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार उक्त प्रकरण के संबंध में भू अभि. निरी. ढाबलाखींची से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण सं. 315/2023 राजस्थान सरकार बनाम गुलाबचन्द बगै के ख.नं. 1256 रकबा 3.1363 है.


उपखण्ड अधिकारी  
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)



किस्म बीड दोगम पर वर्तमान में कोई अवैध खनन नहीं होना पाया गया। वर्तमान में उक्त ख.नं. भूमि मौके पर पडत है। तथा उक्त आराजी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड गुलाबचन्द पि. पुरुषोत्तम हि. 1/2 हर्षवर्धन श्रृंगी पि. ओमप्रकाश श्रृंगी हि. 1/4. रीना श्रृंगी पत्नि अजय श्रृंगी हि. 1/4 जाति ब्राह्मण नि. उन्हेल के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। अतः श्रीमान द्वारा चाही गई मौका/जांच रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

6. प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कोई खनन कार्य नहीं किया गया। वादग्रस्त आराजी उबड खावड एवं कम उपजाउ होने से भूमि सुधार कार्य यथा गढढो की भराई, समतलीकरण, ढलान की खुदाई आदि कार्य किये गये थे ताकि भूमि को उपजाउ बनाया जा सके। उक्त कार्य धारा 66-70 आर.टी.एक्ट के अधीन भूमि सुधार कार्य में आते है। वादी तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण किये बिना पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर यह वाद पेश किया गया है। केवल पटवारी की रिपोर्ट ही वाद पेश करने के लिए विश्वसनीय आधार नहीं हो सकती है। भू धारक तहसीलदार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट कमांक राजस्व/2024/1045 दिनांक 15.10.2024 में स्वयं स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में कोई खनन नहीं हो रहा है। वादग्रस्त आराजी मौके पर पडत पडी हुई है। जब दावा पेश करने वाला भू धारक स्वयं स्वीकार कर रहा है कि वादग्रस्त आराजी पर मौके पर कोई गैर कृषि कार्य नहीं हो रहा है तो फिर शर्तो का उल्लघन या हानिकारक कार्य होना कैसे माना जा सकता है। अतः भू धारक तहसीलदार द्वारा पेश वाद विधि विरुद्ध होने से खारीज फरमाया जावे।

7. भूमि धारक तहसीलदार सुनेल द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में कोई गैर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि अनुपजाउ होने से मौके पर पडत पडी हुई है। तत्कालीन तहसीलदार द्वारा तत्कालीन पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर दायर किया गया था लेकिन वादग्रस्त आराजी पर खनन होने का कोई भी साक्ष्य तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)



6 उपपक्ष की बहस के परिणाम में सर्व प्रथम पटवारी रिपोर्ट, जवाब पत्र, भू धारक की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.10.2024, रजिस्टर रिकार्ड, पेश भूमल फोटोग्राफ्स दिनांक 18.12.2024 आदि को अवलोकन किया गया। भू धारक द्वारा पेश सर्व प्रथम के अनुसार प्रतिवादीगण/खातेदारान द्वारा मानसत आशाती पर खनन कार्य कर भूमि को कृषि अयोग्य बनाने का उल्लेख किया गया है। भू धारक द्वारा यह सर्व प्रथम पटवारी पटवार हल्का उन्हेल एवं भू.अभिलेख निरीक्षक हावलखीची की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.05.2023 के आधार पर तयार किया गया था। उक्त पटवारी रिपोर्ट दिनांक 09.05.2023 में अंकित है कि मौके पर ख.नं. 1256 में खनन होना पाया गया लेकिन मौके पर न ही खनन कार्य संबंधी ध्यान पाये गये और न ही खातेदार उपस्थित पाये गये। अतः यदि खनन कार्य किया गया था तो खातेदारान द्वारा किया गया या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किया गया, यह स्पष्ट नहीं है। मौके पर खनन कार्य होने का कोई भी वस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य वाद पत्र के साथ या सर्व भू धारक द्वारा पेश नहीं किया गया है बल्कि स्वयं भू धारक तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्रांक 1045 दिनांक 15.10.2024 से पेश जाच रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि ग्राम उन्हेल के ख.नं. 1256 रकबा 3.1363 है, किरम बीड वीयम पर वर्तमान में कोई अवैध खनन नहीं होना पाया गया। वर्तमान में उक्त ख.नं. भूमि मौके पर पडत है। स्वयं भूमि धारक ने मौके पर भूमि के पडत होने और किसी प्रकार का गैर कृषि कार्य यानि अवैध खनन कार्य आदि नहीं होना स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण द्वारा पेश ग्राम उन्हेल के ख.नं. 1256, जिसका अक्षांश और देशान्तर क्रमशः 24.340332' & 76.03177' दिनांक 16.12.2024 है— के अवलोकन से जाहिर है कि भूमि अनुपजाउ है और मौके पर पडत पडी हुई है। फोटोग्राफ्स पूरे 3.1316 है, रकबे के होना जाहिर नहीं होता है। प्रतिवादीगण के इस कथन का कि उन्हेने भूमि को उपजाउ व सगतल बनाने के लिए भू सुधार कार्य किये थे— का भू धारक द्वारा बहस के दौरान कोई विरोध नहीं किया गया। भू सुधार कार्य करने के लिए काश्तकार को धारा 66-70 आर.टी.एक्ट में अधिकार दिये गये है। काश्तकारी अधिनियम की धारा 66 व 70 के प्रावधान निम्नानुसार है—

#### 66. Right of Khatedar Tenants to make improvements—

(1) A Khatedar tenant may make any improvement in his holding: **Provided** that the State Government may, from time to time:— (a) restrict, in the public interest, the making of any such improvement as is referred to in sub-clause (a) of clause (19) of section 5 in the areas to be notified for the purpose,

4  
उपस्थित अधिकारी  
पिडवा, जिला झारखण्ड (सज०)



and, (b) make rules to regulate the making of any such improvement in areas not covered by any such notification,

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no sanction shall be necessary for the construction of temporary structures.

(3) Any improvement made in a holding shall form part of the holding.

**70. Right of other tenants to make improvements—** Subject to the restrictions imposed by the 1st and 2nd proviso to sub-section (1) of section 66, a Gair Khatedar tenant or a tenant of Khudkasht. Or a subtenant may make any improvement, but he shall not be entitled to any compensation on ejection unless for making such improvements he has obtained the previous order of the Tehsildar, or the written permission of the holder of Khudkasht or the Khatedar tenant as the case may be.

9. जब खातेदारान प्रतिवादीगण द्वारा काश्तकारी शर्तों के विरुद्ध कार्य व कोई जोत के लिए हानिकारक कार्य किया ही नहीं है तो फिर धारा 177 आर.टी.एक्ट के प्रावधान लागू कैसे होंगे। खातेदारन/प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजी को उपजाऊ बनाने के लिए किये गये समतलीकरण कार्य, गढढो को भरने का कार्य, उबड खाबड ढलान को खोदकर समतल करने का कार्य आदि धारा 66-70 आर.टी.एक्ट के अधीन भूमि सुधार कार्य की श्रेणी में आते हैं जो काश्तकार का अधिकार है। उक्त भूमि सुधार कार्यों को धारा 177 के अधीन **detrimental act or breach of condition** नहीं माना जा सकता है। धारा 177 आर.टी.एक्ट के प्रावधानों का अवलोकन निम्नानुसार है -

**177. Ejection for detrimental act or breach of condition—** (1) A tenant shall on the application of the

उपखण्ड अधिकारी  
राज...



landholder, be liable to ejectment from his holding—(a) on the ground of any act or omission detrimental to the land in that holding or inconsistent with the purpose for which it was let, or (b) on the ground that he or any person holding from him has broken a condition on the breach of which he is, by special contract which is not contrary to the provisions of this Act, liable to be ejected:

Provided that the planting of trees or the making of an improvement in accordance with the provisions of this Act shall not constitute a ground for ejectment under this section.

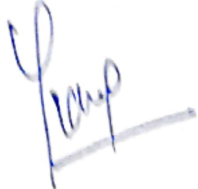
10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर ग्राम उन्हेल के ख.नं. 1256 एकबा 3.1363 है, आराजी के संबंध में चादी भू धारक का चाद अन्तर्गत धारा 177-178 आर.टी.एक्ट न्यायहित में खारीज किये जाने योग्य है।

—ःकियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम उन्हेल के ख.नं. 1256 एकबा 3.1363 है, आराजी के संबंध में भू धारक चादी का चाद अन्तर्गत धारा 177-178 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का खारीज किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(दिनेश कुमार भीणा, आरएएस)  
उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
जिल्सा गझालावाड राज  
पिडावा, जिला झालावाड (राज.)

डिफ़्टी मुकदमा इक्तदाई  
(ओ. 20 रुल 6-7 जाबा दीवानी )  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड(राज.)

बइजलारा - श्री दिनेश कुमार मीना ( आर.ए.एस. )  
प्रकरण सं. 117/2023/राजस्व वाद दायरा दिनांक 04.10.2023

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

- वादी

बनाम

1. गुलाबचन्द पि. पुरुषोत्तम जाति ब्राहमण नि. उन्हेल तहसील सुनेल
2. रीना श्रृंगी पत्नि अजय श्रृंगी जाति ब्राहमण नि. उन्हेल तहसील सुनेल
3. हर्षवर्धन श्रृंगी पि. ओमप्रकाश जाति ब्राहमण नि. उन्हेल तहसील सुनेल

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 177-178 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति -

पेरोकार सरकार - तहसीलदार सुनेल

प्रतिवादीगण/खातेदारान - श्री हुकुमचन्द कुमावत

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिराल कतई रुबरु .....त हाजिरी वकील वादी  
मिनजागिन मुद्दई रुबरु वकील प्रतिवादी मिलजागिन मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व  
डिकी दी जाती है कि

ग्राम उन्हेल के ख.नं. 1256 रकबा 3.1363 है. आराजी के संबंध में भू धारक  
वादी का वाद अन्तर्गत धारा 177-178 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का खारीज  
किया जाता है।

(दिनेश कुमार मीना, आरएएस)

उपखण्ड अधिकारी पिडावा

जिला झालावाड राज०

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमे के शूद वपरिह .....X.....

.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करुंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 10.01.2025 को जारी किया  
गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा

जिला झालावाड राज०

पिडावा जिला झालावाड (राज०)

मुद्दई		मिजान	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिन्गर
स्टाम्प दकालत नाम	फीस कमिन्गर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत्त०
महन्ताना वकील	मुत्त०	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	



(दिनेश कुमार मीना, आरएएस)  
उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
जिला झालावाड राज०  
पिडावा जिला झालावाड (राज०)